



# संपादकीय

## अतार्किक दोहन से बिगड़ता जल – चक्र

खाद्य एवं जल विशेषज्ञों के समूह ग्लोबल कमीशन आन द इकोनामिक्स आफ वाटर की ताजा रपट में पाया गया है कि जल संकट से वैश्विक खाद्य उत्पादन का पचास फीसद से अधिक हिस्सा संकट में है। इससे 2050 तक कई देशों के सकल घरेलू उत्पाद में औसतन आठ फीसद की कमी आ सकती है, जबकि कम आय वाले देशों में यह नुकसान 15 फीसद तक हो सकता है। अनुसार, दशकों से हो रहे विनाशकारी भूमि उपयोग और जल कुप्रबंधन ने मानव जनित जलवायु संकट के साथ मिल कर वैश्विक जल—जल चक्र पर गहरा दबाव बना दिया है। यह कई देशों की अर्थव्यवस्था, खाद्य उत्पादन और जन जीवन पर गहरा संकट सकता है। दुनिया भर में करीब तीन अरब लोग पहले से ही पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। एक तरफ फसलें पानी की कमी से मुरझा रही हैं, तो दूसरी तरफ नगर नगर ढूब रहे हैं। अगर इस संकट को नहीं तो परिणाम भयावह होंगे। सुलझाया गया इस त्रासदी को जल खर्च के संतुलित उपयोग से ही नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए पानी के मोल को पहचानने की जरूरत है। जल चक्र को समझने के लिए इसका वर्गीकरण नीले और हरे पानी में किया गया है। झीलों, नदियों और तालाबों में एकत्रित पानी को नीला पानी कहा जाता है। मिट्टी और पौधों में संचित पानी को हरा पानी कहा जाता है। जल-चक्र उस जटिल प्रणाली को कहते हैं, जिसके द्वारा पानी पृथ्वी के चारों ओर धूमता है। पानी भाष बन कर वायुमंडल में जाता है, जिससे जल वाष्प की बड़ी धाराएं बनती हैं, जो ठंडी एवं संघनित होने के बाद बारिश या बर्फ के रूप में धरती पर गिरती हैं।

हर पानी को आपूर्ति को जिस तरह से नजरअदाज किया जा है, उसे गंभीरता से लेने और सुरक्षित बनाए रखने की जरूरत है। जल चक्र के लिए यह पानी उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना नीला पानी माना जाता है, क्योंकि जब ब पौधे जल वाष्प छोड़ते हैं, तो यह वायुमंडल में चला जाता है, इससे धरती पर होने वाली कुल वर्षा का आधा हिस्सा लौट आता है। दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह भी है कि पेड़-पौधों व वनस्पतियों में प्रदूषण अवशेषित करने की क्षमता निरंतर घट रही रही है। भविष्य में जल चक्र बिगड़ता है, तो भारत में इसका असर कहीं ज्यादा दिखाई देगा। यह स्थिति खाद्य उत्पादन तो घटाएगी ही, पानी की उपलब्धता में भी कमी आ सकती है। दरअसल, हमारी कुछ नीतियां ऐसी हैं, जो जल-चक्र को परिवर्तित कर असंतुलित बना सकती हैं। किसी भी वस्तु में छूट देखने-सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन कृषि के लिए डीएपी खाद पर दी जा रही सबसिडी पानी और राष्ट्र की सकल पूँजी को हानि पहुंचा रही है। दशकों से किसानों को कृषि विभाग और वैज्ञानिक समझा रहे हैं कि नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग खेत में न करें। इससे मिट्टी की उर्वरा क्षमता घटती है और फसलों में पानी भी अधिक लगता है धान, गेहूं, कपास और गन्ना मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर होने पर ज्यादा पानी सोखती हैं। इसीलिए किसानों को मोटा अनाज, दालें व तिलहन पैदा करने और एनपीके खाद डालने को कहा जाता है। मगर एनपीके पर सबसिडी न होने के कारण यह खाद महंगी मिलती है। नतीजतन, किसानों ने इसे लगभग खारिज कर दिया है। सरकार डीएपी पर सबसिडी इसलिए दे रही है कि उसे राजनीतिक हानि न उठानी पड़े। यूरिया डीएपी पर प्रतिवर्ष लगभग दो लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रत्यक्ष सबसिडी दी जाती है। इस कारण धान और गेहूं की फसल ज्यादा उगाई जाती है, क्योंकि ये फसलें ज्यादा मात्रा में पैदा होती हैं और इन्हीं का ज्यादा निर्यात होता है। तमाम प्रोत्साहन के बावजूद किसान बहुफसलीय खेती करने से भी कतरा रहे हैं। इस वजह से देश को दलहन और तिलहन बड़ी मात्रा में आयात करने होते हैं। इनके आयात में बड़ी मात्रा में विदेश पूँजी भी खर्च होती है। यही नहीं, गेहूं-चावल की फसलों में जल प्रबंधन और विजली व्यवस्था में जो धन खर्च होता है, वह भी अप्रत्यक्ष निर्यात के जरिए नुकसान का सबब बन रहा है। मगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इस हकीकत का न तो खुलासा होता है और न ही विपक्ष इन मुद्दों को संसद में उठाता है। खेती और कृषिजन्य औद्योगिक उत्पादों से जुड़ा यह ऐसा मुद्दा है, जिसकी अनदेखी के चलते पानी का भी निर्यात हो रहा है। इस पानी को श्वर्चुअल वाटरश भी कह सकते हैं। दरअसल, भारत से बड़ी मात्रा में चावल, चीनी, वस्त्र, जूते-चप्पल और फल व सब्जियों का निर्यात होता है। इन्हें तैयार करने में बड़ी मात्रा में पानी खर्च होता है। अब । तो जिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने हमारे यहां बोतलबंद पानी के संयंत्र लगाए हुए हैं, वे भी इस पानी को अरब देशों को निर्यात कर रही हैं। इस तरह से निर्यात किए जा रहे पानी पर लगाम नहीं लगाई गई तो संकट और बढ़ेगा। जबकि देश के तीन चौथाई घरेलू रोजगार पानी पर निर्भर हैं। आमतौर शुद्ध पानी, तेल और लोहे यह भुला दिया मूल्यवान लोहे की तुलना में कहीं क्योंकि पानी पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में बीस हजार डालर प्रति हेक्टेयर की दर से सर्वाधिक योगदान करता करता है। इस दृष्टि भारत कृषि और इससे संबंधित उत्पादों के जरिए पानी का जो अप्रत्यक्ष निर्यात हो रहा है, वह हमारे भूतलीय और भूगर्भीय दोनों ही प्रकार के जल भंडारों का दोहन करने को बड़ा सबब बन रहा है। दरअसल, एक टन अनाज उत्पादन में एक हजार टन पानी की आवश्यकता होती है। धान, गेहूं कपास और गन्ने की खेती में सबसे ज्यादा पानी खर्च होता है। इन्हीं का हम सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं।

# जटिल फॉर्म और आईटी प्रक्रियाओं में सुधार

ललित

कुरुपता, अपराध और आपदा दार्शनिकों को सृष्टि के सिद्धांतों का स्वामी घोषित करते हैं। यदि इन विनों का श्रेय ईश्वर को दिया जाता होगा क्योंकि मुझे नवंबर के मध्य में स्पेन से वापस आया, और अब सोचा कि मुझे एक नया पासपोर्ट और एक नया ओसीआई कार्ड प्राप्त करना होगा क्योंकि मुझे नवंबर के मध्य में स्वदिविनी आयी थी।



मुंबई में टाटा लिटरेरी फेस्टिवल  
और फिर एक सप्ताह बाद गोवा  
फिल्म फेस्टिवल में एक  
सास्टर-क्लास आयोजित करने के

ए आमंत्रित किया गया इसे तुरंत  
कार कर लिया गया और पांच  
मीनों के भीतर डाक से नया पासपोर्ट  
गया। और फिर छ व्ह कार्ड की  
एक शुरू हुई। मैंने छवहसम से

# वित्तीय रक्षाशाली के सपने संजोना

विश्व बचत दिवस, जिसे दुनिया में 31 अक्टूबर और भारत में 30 अक्टूबर को मनाया जाता है, वित्तीय ध्यान में बचत की महत्वपूर्ण भूमिका ध्याद दिलाता है। इटली के मिलान 1924 में स्थापित, यह दिवस भूमिका के महत्व पर जोर देता है और बचत करने की आदत विकसित करता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 1984 में इसे अक्टूबर को मनाया गया। जब गांधी इस दिन का सम्मान करने लिए एक साथ आती है, तो वे न ल पैसे बचाने के कार्य पर जोर हैं, बल्कि वित्तीय विवेक, सुरक्षा व बेहतर भविष्य की आशा के पक मूल्यों पर भी जोर देते हैं। व बचत दिवस लोगों को संसाध को बुद्धिमानी से प्रबंधित करने लाभों को पहचानने के लिए प्रेरित ता है, वित्तीय साक्षरता की संस्कृता को बढ़ावा देता है जो अब ताली

पीढ़ियों को सशक्त बना सकता है। भारत सरकार बचत की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, जित मंत्रालय समाज की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बचत उत्पादों की एक विविध श्रृंखला पेश करता है। प्रत्येक योजना न केवल एक वित्तीय उपकरण के रूप में कार्य करती है, बल्कि अधिक सुरक्षित भविष्य की ओर एक कदम के रूप में भी कार्य करती है। इन बचत योजनाओं का संरक्षक, राष्ट्रीय बचत संस्थान वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास करता है। एक चहल-पहल वाले डाकघर की कल्पना करें जहाँ परिवार खाते खोलने, अपने सपनों में निवेश करने और अप्रत्याशित क्षणों के लिए सुरक्षा जाल बनाने के लिए आते हैं। छौं राष्ट्रीय स्तर के अभियानों में संलग्न है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर कोई बचत के लाभों को जानता है, चाहे वह बच्चे की शिक्षा के लिए हो या आरामदायक सेवानिवृत्ति के लिए। इनमें डाकघर बचत खाता भी शामिल है, जो व्यक्तियों को ₹500 की न्यूनतम जमा राशि के साथ बचत शुरू करने के लिए आमंत्रित करता है और ₹10,000 तक की राशि पर कर-मुक्त ब्याज प्रदान करता है। परिवार अक्सर राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा खाता चुनते हैं, जो अनुशासित मासिक योगदान को प्रोत्साहित करता है, जिससे उन्हें अपनी आकांक्षाओं के लिए हर महीने केवल ₹100 की बचत करने की अनुमति मिलती है। दीर्घकालिक सुरक्षा का सपना देखने वालों के लिए, सार्वजनिक भविष्य निधि योजना 15 वर्षों में बचत को बढ़ावा देती है, कर-मुक्त ब्याज और निकासी और ऋण के लिए लचीलापन प्रदान करती है। हाल ही में लॉन्च किया गया महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, 7.5: प्रति वर्ष की उच्च ब्याज दर के साथ महिलाओं को सशक्त बनाता है, जिससे अपनी बेटियों के भविष्य में निवेश करने के इच्छुक परिवारों में उत्साह पैदा होता है। इस बीच सकल्ला समटि खाता

A photograph showing three stacks of Indian rupee coins arranged horizontally. The stack on the left is the shortest, the middle one is taller, and the stack on the right is the tallest. They are placed on a light-colored surface against a blurred green background, representing the concept of saving money over time.



A photograph showing a close-up of a person's hand holding a single coin above a clear glass jar. The jar is partially filled with coins and has the word "SAVE" handwritten on its side in capital letters. The background is blurred, showing some greenery, which suggests an outdoor setting like a garden or a park.

# भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण

विनोद समिति द्वारा अनुशंसित राष्ट्रीय नीति (एनईपी) 2020 की आत के साथ भारत का शिक्षा दृश्य एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से बदल रहा है। जुलाई 2020 में केंद्रीय बमेडल द्वारा अनुमोदित इस हासिक नीति का उद्देश्य प्रारंभिक पन से लेकर उच्च शिक्षा तक बने में समावेशिता, गुणवत्ता और अंगिकता सुनिश्चित करते हुए देश शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव ना है। इस व्यापक गाइड में, हम एनईपी 2020 की मुख्य विशेषताओं निहितार्थों पर प्रकाश डालेंगे, जिनमें भारत में शिक्षा के भविष्य को धार देने की इसकी क्षमता की ज़रूरत करेंगे। एनईपी कब लागू होगी? एनईपी को 2023–2024 शैक्षणिक के दौरान लागू किया जाना चाहिए हुआ। इसे भारत के सभी राज्यों द्वारा केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा लागू कराया जाएगा। इससे क्या बदलाव होगा? एनईपी ने विभिन्न बदलाव दिये, जिनमें पाठ्यक्रम में अपडेट, संरचना में संशोधन और भारतीय सेक प्रणाली के कामकाज में विभूत परिवर्तन शामिल हैं। एनईपी लक्ष्य क्या हासिल करना है? एनईपी का लक्ष्य कई प्रवेशधनिकास कल्पों के साथ एक समग्र –विषयक शिक्षा बनाना है जो विभिन्न विषयों के बीच रचनात्मकता और संसंगत सोच को बढ़ावा देता है। एनईपी परीक्षाओं को पूरी तरह समाप्त कर देता है, या उन्हें नया रूप देता है? जबकि कक्षा 10 से 12 की बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी, चेंग कक्षाओं की आवश्यकता को कम करने के लिए उन्हें फिर से नाइन किया जाएगा। छात्र अपनी विषयों के आधार पर विषयों का चयन सकते हैं, और परीक्षा याद रखने वजाय मुख्य कौशल पर केंद्रित होती है। परीक्षाएं भी आसान होंगी, जिससे छात्र बुनियादी प्रयास से उत्तीर्ण सकेंगे। इसके अतिरिक्त, विषयकता पड़ने पर छात्र सुधार लिए वर्ष में दो बार परीक्षा देते हैं। अब, आइए राष्ट्रीय शिक्षा

नीति पर करीब से नजर डालें। यह व्यापक विश्लेषण आपके सभी प्रश्नों का समाधान करेगा और एनईपी में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। एनईपी 2020 की नींवरु समावेशी और न्यायसंगत शिक्षारू समावेशी शिक्षा पर एनईपी का ध्यान सतत विकास लक्ष्य 4 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि या क्षमताओं के बावजूद, सभी शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करना है। एनईपी हाशिए पर रहने वाले समुदायों, जैसे कि लड़कियों और विकलांग बच्चों, को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के महत्व पर जोर देती है। गुणवत्ता और प्रासंगिकतारू 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने, आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। एनईपी छात्रों को भविष्य के कार्यबल के लिए व्यावहारिक कौशल से लैस करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा और अनुभवात्मक शिक्षा के एकीकरण की वकालत करता है। एनईपी 2020 की मुख्य विशेषताएं रु वर्तमान में, 102 शैक्षिक संरचना में 3-6 वर्ष की आयु के बच्चे शामिल नहीं हैं, क्योंकि औपचारिक स्कूली शिक्षा आम तौर पर कक्षा 1 के साथ 6 साल की उम्र में शुरू होती है। हालांकि, नए 5334 दृष्टिकोण के तहत, प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एकीकृत है, जिसका लक्ष्य शुरुआती चरणों से ही उन्नत शिक्षा, विकास और कल्याण को बढ़ावा देना है। प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) रु एक बच्चे के मस्तिष्क का 85: से अधिक संचयी विकास 6 वर्ष की आयु से पहले होता है, जो स्वरूप मस्तिष्क के विकास और विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक वर्षों में मस्तिष्क की उचित देखभाल और उत्तेजना के महत्वपूर्ण महत्व को दर्शाता है। एनईपी 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए

ई तक थिकिंग और व्यावसायिक कौशल जैसे आधुनिक विषयों को जोड़ना शामिल है। डिजिटल कौशल जैसे कोडिंग और कंप्यूटर को समझना। पर्यावरण शिक्षा भी शामिल होगी। आकलन और मूल्यांकन रुपयता—आधारित मूल्यांकन रुपयता—आधारित मूल्यांकन की ओर बदलाव। एनईपी वार्षिक रिपोर्ट कार्ड से समग्र प्रगति कार्ड में परिवर्तन का प्रस्ताव करता है रचनात्मक मूल्यांकन प्रथाएँ रुपयता पर प्रतिक्रिया प्रदान करने और छात्रों के सीखने में सहायता करने के लिए रचनात्मक मूल्यांकन प्रथाओं को प्रोत्साहित करना। सहकर्मी मूल्यांकन, स्व-मूल्यांकन और फीडबैक—उनमुख मूल्यांकन छात्रों को अपने सीखने का स्वामित्व लेने और अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए सशक्त बना सकते हैं। छात्रों की अद्वितीय प्रतिभा को प्रोत्साहित करनारु प्रत्येक छात्र में अद्वितीय प्रतिभाएँ होती हैं जिन्हें खोजने और निखारने की आवश्यकता होती है। यदि कोई छात्र किसी निश्चित क्षेत्र में असाधारण योग्यता दिखाता है, तो उसे आगे खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षक उन विषयों में अतिरिक्त सामग्री और प्रोत्साहन प्रदान करेंगे जिनके प्रति छात्र भावुक हैं। इसमें विज्ञान या गणित मंडल, संगीत और नृत्य प्रदर्शन, शतरंज, कविता, भाषाएँ, नाटक, वाद-विवाद, खेल, या इको और योग क्लब जैसी गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं। शिक्षक—छात्र अनुपात: वर्तमान शिक्षक—छात्र अनुपात रु यूनेस्को के अनुसार, भारत में शिक्षक—छात्र अनुपात लगभग 1.032 है, जो अतिरिक्त शिक्षण स्टाफ की आवश्यकता को उजागर करता है। आदर्श शिक्षक—छात्र अनुपात एनईपी का लक्ष्य व्यक्तिगत ध्यान और प्रभावी सीखने के परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में शिक्षक—छात्र अनुपात को 1.025 तक कम करना है। शिक्षक सशक्तिकरण

शिक्षा प्रथाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से 100: युवा और वयस्क साक्षरता हासिल करना है। प्रौद्योगिकी की भूमिकारू डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चररू अॉनलाइन शिक्षण और शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच का समर्थन करने के लिए मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया सभवमन प्लेटफॉर्म विभिन्न संस्थानों से मुफ्त अॉनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जो देश भर के शिक्षार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करता है। मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार होगा डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर्म नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा) पर उपलब्ध। कराया गया। कस्तूरीरंगन समिति और उसकी सिफारिशों रूप कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों से प्रभावित थी, जिसने शिक्षा क्षेत्र में चुनौतियों का समाधान करने के लिए व्यापक सुधारों का प्रस्ताव रखा था। सिफारिशें लागू की गईं रूप कस्तूरीरंगन समिति की कई सिफारिशें, जैसे स्कूली शिक्षा का पुनर्गठन और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर, को एनईपी में शामिल किया गया है। एनईपी 2020 पिछली नीतियों से कैसे अलग है? पिछली शिक्षा नीतियां मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित थीं कि हर किसी की शिक्षा तक पहुंच हो। नई नीति उन लक्ष्यों को संबोधित करती है जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूरी तरह से हासिल नहीं किए गए थे, जिसे 1992 में अद्यतन किया गया था। तब से एक महत्वपूर्ण बदलाव बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, जिसने सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना एक कानूनी आवश्यकता बना दिया है। निष्कषरू राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत में शैक्षिक सुधार के एक नए युग की शुरुआत करती है।

# मर्म और आमंत्रित

# र आईटी प्र

की तस्वीर और कुछ व्यक्तिगत  
विवरण की आवश्यकता नहीं थी।  
इसमें मुझसे चोरी के बारे में पुलिस  
को दी गई मेरी रिपोर्ट की एक प्रति  
मांगी गई। मैं पुलिस स्टेशन गया  
और उसके बाहर आईटी प्र की तस्वीर

अगला सवाल था भूल ?  
साथ संबंधपूर्ण क्या??? मैंने  
चुना और घिप्ताष भर दिया।  
फॉर्म में न केवल मेरा  
पासपोर्ट नंबर बल्कि मेरे

# क्रियाओं

तीय के टेडी को । फिर वर्तमान पिछले हैं। तस्करी / बाल शोषण / महिलाओं के खिलाफ अपराध / आर्थिक अपराध / जासूसी / नरसंहार / साइबर अपराध / वित्तीय दोषों खादी अड़ी / आतंकवादी गतिविधि

# में सुधार

त की मदद लेनी चाहिए जो आईटी-वाला था और इसलिए बाद में फॉर्म भरना फिर से शुरू ना होगा। मैंने ब्बाद में फिर से करेंगे विकल्प दबाया और एक साथ चार घंटे बिताए और वही समस्याएँ झोलीं, लेकिन आखिरकार सभी दस्तावेज अपलोड और भेजे गए। बढ़िया! मुझे अगले दिन भारतीय उच्चायोग के वीजा जारी करने वाले हैं।

आर एक कापा ल आया। पहला कदम पूरा हुआ। फिर फॉर्म में मेरा नाम, लिंग, तारीख, जन्म का देश और शहर पूछा गया। फिर इसमें व्यहचान के निशाने के बारे में पूछा गया। मैंने इसका मतलब समुद्री डाकू की आँख पर पट्टी से नहीं लिया जिसे मैं अपने समुद्री झुकाव को दिखाने के लिए लगातार पहनता हूँ, बल्कि यह कि क्या मेरी भौंहों के बीच बिंदी जैसा लाल जन्मचिह्न है। मैंने कहा छोई नहीं। फिर मेरे पिता का नाम और पेशा (?) और निश्चित रूप से उनकी दोनों राष्ट्रीयताएँ।

य आर  
ना मांगा  
पसे 16  
बेतुके  
गयारू  
वरसीज  
सरेंडर  
या है?"  
क ऐसा  
गुरुआत  
माने या  
होती है,  
जवाब  
पसिद्धि,  
पर्याँच की

या / राजनातिक हत्या / इसा क  
अन्य कृत्यों में संलिप्तता के बारे में  
अन्य सवाल थे? नरसंहार?? क्या  
पुतिन या नेतन्याहू व्ह कार्ड के लिए  
आवेदन कर रहे हैं? फिर फॉर्म में  
"सेक्शन बी" में एक फोटो और  
हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए  
कहा गया। मैंने दोनों को अपलोड  
करने की कोशिश की, जो मेरे कंप्यूटर  
में संग्रहीत थे, लेकिन बार-बार कहा  
गया कि उनमें से कोई भी आकार  
और गुणवत्ता के लिए बहुत अस्पष्ट,  
अकल्पनीय (आखिरकार मेरे द्वारा)  
तकनीकी विनिर्देशों के अनुरूप नहीं  
था। मझे लगा कि मझे एक ऐसे



